[Shri K. C. Pant]

being done. So, this covers the entire area. Although I have more material with me I do not want to trespass on the time of the House. After this explanation of the reasons for bringing forward this motion I hope the House will accept it unanimously.

श्री नवल किशोर : पन्त जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया लेकिन एक काम आप और कर दें कि जो आपके सरीन साहब वहां हैं उनको इतना एडवाइस कर दें कि प्रेसीडेन्ट रूल में थोड़ा डेमोक्रटिक वे में काम करना शुरू कर दे तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि वे "निजाम" बन कर वहां जाते है, जो कि मुनासिब बात नहीं है ।

SHRI M. R. KRISHNA : This is not fair. The Adviser there is not acting like the Nizam. He is acting more like a commoner available to everybody. He is really doing very good work there. I think you are a little unfair.

SHRI NAWAL KISHORE: He should behave democratically.

(Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Leave it at that stage.

The question is :

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 18th January, 1973, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Andhra Pradesh, for a further period of six months with effect from the 1st September, 1973."

The motion was adopted.

STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL FOR CONTINUANCE OF THE PROCLAMATION UNDE* ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO THE STATE OF MANIPUR

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : Sir, I beg to move the following Resolution :

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 28th MJirch, 1973, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Manipur, for a further period of six months with effect from the 14thj November, 1973".

The circumstances under which the Proclamation dated the 28th March, 1973 was issued by the President are well known to the Members of the House. The justification for President's Proclamation had been debated in this House on two earlier occasions and it would not be necessary for me to recall the points made during those debates. The House is aware that the Legislative Assembly | of Manipur had been dissolved and that elections cannot be held until the (constituencies have been delimited and fresh electoral rolls, etc. have been prepared. These preliminary measures for holding the elections are being expeditiously pursued by the Election Commission. We all hope that these preliminaries will be completed in the course of the year and elections would be held early next year. But meanwhile there cannot be a vacuum. The period for which the House had earlier accorded its approval for the continuance of the Proclamation will expire when the House may not be in session. Therefore, we have come to this Housie with a request that the duration of the Proclamation made by the President may be further extended for a period of six months. Such an extension is constitutionally unavoidable and therefore I would request the House to accord its approval to the Resolution. The Hoiise is aware that Members of this House as well as the other House had recently discussed in another forum a large number of matters relating to Manipur^ We look forward to this

deflate because Parliament should provide* the lead to the administration, particularly when a State is under President's rule. I would not like to anticipate the debate. We have already circulated a brief report indicating the various problems taken up by the administration during President's rule

As I have stated earlier, Sir, the extension of the duration of the Proclamation is unavoidable. I would, therefore, again request the House to aprove the Resolution.

The question was proposed.

SHRI SALAM TOMB1 (Manipur) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to oppose the President's rule. President's rule cannot be a substitute for democratic rule. It can never be a substitute for popular government. It is the rule of the bureaucrats. The Government have said that elections would be held early next year. I hope that this is the first and last extension of President's rule in Manipur. In Manipur all the key posts are generally held by non-Manipuris. In Orissa, in U.P. and in Andhra I think they have got their own local people in key posts. In Manipur we have got the pangs of President's rule. There is none in the administration who knows Manipur and who thinks generously about the welfare of Manipur.

The first casualty of the Presidents rule in Manipur is that we have got only eleven seats in the Manipur Medical College out of 50. When we have no college, we have more than double the number of seats, but when we have got a college we have got only eleven seats out of fifty. This is the first casualty of the President's rule. In today's discussion about bandhs, from the Government side it was said that any bandh is anti-national and anti-people. But this extension of the President's rule again and again will force us to organise bandhs in a bigger way. Let them call it anti-national, anti-people. We never cease the struggle for our aspirations. Manipur should be ruled by Manipuris, not by any other people.

Thank you.

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, ऐसा दिखलाई दे रहा है कि राष्ट्रपति शासन और प्रदेशों के झगड़े देश के ऊपर छा गये हैं। अभी हम थोड़ी देर हुए आन्ध्र में राष्ट्रपति शासन चालू रखने के बारे में चर्चा कर रहे थे। और अब यह मणिपुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद उड़ीसा मे राष्ट्रपति शासन चालू रखने के बारे मेचर्चा होगी। कल हम उत्तर प्रदेशों के बारे मे काम कर चुके हैं। सब प्रदेश की सरकारों मे झगड़ों की हालत यही है।

कुछ दिन हुए बिहार और गुजरात मे भी आपसी झगड़े हुए थे, लेकिन वे राष्ट्रपति शासन से बाल बाल बच गये। मध्यप्रदेश और दिल्ली में आपसी झगड़े हुए थे, फिलहाल उन्हें इंजेक्शन लगाकर रोक दिया गया है। यह देखना है कि इस इंजेक्शन का असर कब तक रहता है। मैसूर मे भी झगड़े के बादल उमड़ रहे है। हरियाणा के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में इस सदनमें काफी चर्चा हो चुकी है। पंजाब में अभी जमीन के ऊपर मंत्री, स्पीकर और जाने किस किस का झगड़ा चल रहा है।

इन सब झगड़े का एक ही इलाज मालूम होता है जो दीक्षित जी के पास है। जहां भी झगड़ा हो, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाय। श्रीमन 1972 के चुनाव में बहुत प्रमुखता से यह बात कही गई थी कि केन्द्र में जिस पार्टी का शासन हो, अगर उसी पार्टी का शासन प्रदेशों में भी हो, तो इससे स्टैबिलिटी आ जायगी, स्थयित्व आयेगा। जनता ने विश्वास करके 1972 में चुनाव हुए थे जिन प्रदेशों में, उनमें कांग्रेस की सरकार बनवायी थी।

केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है और प्रदेशों में भी कांग्रेस की सरकार है परन्तु इन-स्टैबिलिटी फिर भी बहुत दिखाई देती है। इसका इलाज केवल राष्ट्रपति शासन सामने लाया जाता है। चलो प्रदेशों में तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, केन्द्र में क्या करेंगे ? आज देश की जो हालत है उसमे केन्द्र की समस्याएं भी कुछ कम नहीं है। चीजों की कीमतें बढ़ती चली जा

[श्री पीतांबर दास]

रही है, रुक नहीं पा रही है, साधारण आदमी के लिए जिन्दगी बिताना भी मुश्किल हो रहा है। बेकारी और बरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। चीजें मिलनी बन्द हो गई हैं, पैसे लिए फिरते रहो, चीजें मिलती नहीं। शांति और व्यवस्था की यह हालत है कि कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन अखबार में कत्ल और लूटमार की घटनाएं पढ़ने को न मिलती हों। दिल्ली तक के अन्दर दिन-दहाड़े खुले आम कत्ल हो जाते हैं और सशस्त्र पहरेदारों की आंखों के सामने बैंकों तक से लाखों की चोरी हो जाती है। तो आखिर क्या अन्जाम इसका होने वाला है? बताया यह जाता है कि "Alternative to the Congress *rule* is chaos." और दिखाई यह देता है कि Continuance of the Congress rule is leading the country towards chaos. आखिर इन सब चीजों का इलाज क्या है? मैं खास तौर से पंतजी के सामने यह सवाल इसलिए रख रहा हूं कि उनके पास गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय सम्भालने के गुण उन्हे विरासत में मिले हैं। दीक्षित जी से मैं अपील इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वे मुल्क की सियासी जोड़तोड़ में, उठक-पठक में, तोड़ फोड़ में व्यस्त रहते हैं।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उनका तोड़ फोड़ से क्या वास्ता, वे तो जोड़ करते हैं।

श्री पीताम्बर दास : विरोधी दलों में तोड़ फोड़ की भी कोशिश करते हैं। पन्त जी सब इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूं क्योंकि मैं इन सब उलझनों से बचे हुए दिखाई देते है। इसलिए वे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। आज नवल किशोर जी ने दीक्षित जी का नामकरण किया है। क्या कहा है भाई? "हैंगमेन आफ डेमोक्रेसी . . ."

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) । मैंने यह

"I would request Pantji to «advice Dikshitjji to function in a way that history may not be forced to give an adverse verdict against him and say that he was the hangman of democracy in India."

श्री पीताम्बर दास : अच्छा। तो मैं नवल किशोर जी से केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं। अगर उन्हें शब्द ही प्रयोग करना था तो दीक्षित जी के पद का मान-मर्यादा का ध्यान रख कर किया होता। अगर कहना ही था तो बजाय "हैंगमेन आफ डेमोक्रेसी" के "लार्ड एग्जीक्यूशनर आफ डैमोक्रेसी" कहते।

श्री रणबीर सिंह : नहीं सेवियर आफ डेमोक्रेसी।

श्री नवल किशोर : तुम तो यही कहोगे।

श्री रणबीर सिंह : तुम दूसरा कहोगे।

श्री पीताम्बर दास : केन्द्र में जब ये सारी परेशानियां हैं तो उसका इलाज मैं जानना चाहता हूं पन्त जी से कि वे अपने मन मे क्या सोच रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के एक प्रमुख सदस्य ने एक उपाय सुझाया है और वह है लिमिटेड डिक्टेटरशिप का।

श्री रणबीर सिंह : उसका जवाब प्रधान मंत्री जी ने दिया है।

श्री पीताम्बर दास : किसने दे दिया है?

श्री रणबीर सिंह : प्रधान मंत्री ने कह दिया है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : इरादा होगा तब भी नहीं चलने देंगे।

श्री पीताम्बर दास : कहां कहा है, जरा मैं जानना चाहता हूं।

श्री रणबीर सिंह : अभी फ्रीडम फाइटर्स की एसोसिएशन की मीटिंग थी जिसको इनआगोरेट किया है प्राइममिनिस्टर ने। वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने शशि भूषण जी का नाम लेकर के वह बात कही।

श्री नवल किशोर : वह तो कल अखबार मे छपेगा ।

(Interruption)

श्री पीताम्बर दास : मैं तो अभी तक की बात कह रहा हूं । यह सुझाव कल नहीं आया है । यह सुझाव तो काफी दिन पहले से आया हुआ है । तब से अब तक की खामोशी के माने क्या मैं नीमरजा समझूं ? आखिर तब से अब तक कोई उनका कन्ट्रोडिक्शन ने सरकार की तरफ से आया है, न कोई प्रतिक्रिया पार्टी की व्यक्ति है । अगर उस लिमिटेड डिक्टेटरशिप में ही जाना है तो बैठ करके तय कर लीजिए कि हमारे बड़े बड़े लोगों ने जो देश के लिए प्रधान तन्त्रीय पद्धति अपनाई थी, कान्स्टीटयुशन बनाया था वह गलत हुआ ई । मैं पन्त जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उस कान्स्टीटयूशन बनाने वाले लोगों में मैं नहीं था । हमारे बुजुर्ग और उनके पिता जी थे । अगर उनके बनाये हुए कान्स्टीटयूशन को वह बदलना चाहें तो वह शोक से बदल दें । वे एक कांस्टीटूएंट असेंबली दूसरी बना ले और वह तय कर दे कि देश के अन्दर डिक्टेटरशिप चलेगी । वह लिमिटेड डिक्टिटरशिप हो, या अनलिमिटेड डिक्टेटरशिप हो, लेकिन हमें इस बारे में निश्चित हो जाना चाहिए । हमें अपने माइंड को साफ कर लेना चाहिए कि हम देश को ले जाना किधर चाहते है ।

गृह मंतामय उनके पास है । अपने देश की इस बिगड़ती हुई परिस्थिति को संभालने की वे कोशिश करें। उन्होंने राष्ट्रपति शासन एक प्रदेश में लागू कर दिया, दो प्रदेश में लागू कर दिया, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है । मैं चाहूंगा कि पन्त जी इस संबंध में जो उनके मन में विचार उठते है उनको बताने की कृपा करें।

श्री गोलाप बरबोरा (आसाम): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज दिन में लगातार कई प्रांतों में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में बहस चल रही है चाहे वह आन्ध्र प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो या मनीपुर में हो । राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में भी है । जहां तक विधान सभाओं को भंग करने का सवाल है, हम देखते हैं कि जहां जहां कांग्रेस मेजोरिटी में रही, वह चाहे आन्ध्र प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों में असेंबलीज एनीमेटेड सस्पेंशन में हैं । उड़ीसा में जहां कि नन्दिनी सत्पथी की सरकार की ताकत बिल्कुल हट गई थी, वहां वहां असेंबली को डिजाल्व कर दिया । मनीपुर में भी कांग्रेस गलत तरीके से मेजोरिटी पाने की कोशिश कर रही थी और पा नहीं सकी तो असेम्बली को डिजाल्व कर दिया । मेजोरिटी पाने के लिए वहां पर इतना तक हुआ कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर, सी० आर० पी० तक को लेकर दो तीन एम० एल० एज० को बाहर कहीं बन्द करके उन लोगों ने वोटिंग कराने की कोशिश की । मनीपुर में यह हालत होने की बात ही वैसी है । वहां की कमजोर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दो खम्भो पर खड़ा होने की कोशिश की । एक खम्भा वहां का पहाड़ी नेता रेसांग का सांग है और दूसरा खम्भा है दिल्ली में रहने वाला एक रोविंग कांग्रेसी नेता शीलभद्र याजी जी जो मनीपुर और मिजोरम वगैरह मे कांग्रेस को बचाने की कोशिश में घूमते हैं । शीलभद्र याजी जी के लिए मेरे दिल मे सम्मान है क्योंकि आजादी के आंदोलन मे वह पहली बार कतार में थे और नेताजी सुभाष चन्द्र जी के साथी थे लेकिन मनीपुर जा करके कांग्रेस को संभालना दिल्ली मे रह कर वह बहुत मुश्किल है । रेसांग कोसांग पहले सोशलिस्ट पार्टी में थे और 1957 से 1962 तक संसद में आ गये थे । डा० राम मनोहर लोहिया जी ने उन को काफी बढ़ावा दिया था । 1962 के चुनाव में हारने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में खप नहीं पाये । फिर वें कांग्रेस से निकले और उस के बाद उन्होंने नागा इंटीग्रेशन कौंसिल बना कर मणिपुर के कुछ पहाड़ी इलाकें को नागा लैंड के साथ शामिल करने का एक स्लोगन लगा कर उन्होंने एक ताकत खड़ी की और अभी जब मणिपुर में कांग्रेस की मेजारिटी नहीं थी तो उस समय यह कोशिश की गयी शीलभद्र याजी और दूसरे नेताओं की तरफ से कि रेसांग कोसांग को चीफ मिनिस्टर बनने का लालच दे कर उन को अपनी तरफ बुलाया जाया उन को कहा गया कि तुम 5, 7 आदमी ले कर कांग्रेस में आ जाओ । लेकिन वे सात आदमी ले कर भी कांग्रेस में नहीं आ पायें और तब कांग्रेस को मेजारिटी में लाने की कोशिश चीफ सेक्रेटरी

[श्री गोलाप बरबोरा]

द्वारा और सी० आर० पी० द्वारा की गयी और उस में भी जब सफलता नहीं मिली तब वहां की असेम्बली डिजाल्व हुई ।

मणिपुर एक छोटासा प्रांत है । वहां की 11 लाख की आबादी है । जैसे पश्चिम में गोआ है, बहुत सुन्दर छोटा सा प्रांत, उसी तरह से मणिपुर पूर्व में है । लेकिन अगर हम गोआ से मणिपुर को कंपेयर करें तो देखेंगे कि गोआ पोर्तुगीज जमाने में जितना डेवलप हो चुका था आजादी के 25 साल में भी मणिपुर उतना डेवलप नहीं हो पाया है । गोआ बहुत सुन्दर है, वहां काफी बरसात होती है, वहां हर गांव तक पहुंचने के लिये रोड है । लेकिन मणिपुर में नहीं है । मणिपुर में आज तक पावर की कोई व्यवस्था नहीं है । एक लोकटक प्रोजेक्ट लगाने की बात हम काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कब तक वह प्रोजेक्ट कामयाब होगा, कब तक वहां बिजली बनने लगेगी इस का कोई जवाब सरकार से नहीं मिलता । मणिपुर के लोग कृषि में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं । मणिपुर की जो भाषा है वह देश की रिकग्नाइज्ड भाषाओं में नहीं है, लेकिन आप इंफाल में जा कर देखिये, उन की लाइब्रेरी में, उन के म्यूजियम में जो किताबें हैं वे बहुत काफी है और मैं आसाम से आता हूं । असमी भाषा डेढ़ करोड़ लोगों की भाषा है, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत से क्षेत्रों में भले ही मणिपुरी भाषा असमिया से पीछे नहीं है । मणिपुर का लोक नृत्य मशहूर है । मणिपुर की हर औरत तांत बुनती है । मणिपुर में बुनकरों का कोई अलग वर्ग नहीं है । वहां हर औरत तात बुनती है, लेकिन आज यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की धांधली से सूत के बारे में जो उन की नीति है उस की तकलीफ मणिपुर सब से ज्यादा महसूस कर रहा है । वहां की बिजिनेस कम्युनिटी अलग नहीं है । वहां हर घरकी औरत तांत बुनती है और उस को सूत नहीं मिल रहा है । और जो कुछ वह तांत से बुनते हैं उस की मार्केटिंग की व्यवस्था ठीक से नहीं है । मणिपूर एक ऐसी जगह है कि जहां कोई इंडस्ट्री नहीं है । मणिपुर के लोग काफी उद्योगी हैं । जितने लोग वहां मणिपुर में रहते हैं उतने ही मणिपुर बाहर के प्रांतों में, आसाम में, त्रिपुरा में, बंगाल में बसे हुए हैं और वे मेहनतकश लोग हैं । वे खेतिहर हैं वे इंजिनियरिंग का काम जानते हैं, वे अच्छे स्पोर्टस्मैन हैं, लेकिन वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है । अगर वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तो मणिपुर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता । वहां एक ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है जिस में वहां के लोगों में ऐंटी सेंटर फीलिंग है । और ईस्टर्न रीजन के बहुत से इलाकों में यह चीज है । वहां के लोग कर्मठ हैं, शिक्षित हैं, लेकिन जिन्दगी में उन को कोई मौका नहीं मिल रहा है । वहां दो चार पांच अफसर हैं, लेकिन ज्यादातर दिल्ली से लोगों को ले जा कर काम चलाया

5 P.M.

जाता है । यह हालत मनीपुर के लोगों की है और आज सेन्टर के हाथ में मनीपुर का प्रशासन है और उसको 6 महीने के लिए फिर से एक्सटेन्ड करने आप जा रहे हैं । मैं तो चाहता हूं कि छोटे से इस प्रांत में ऐसा कोई सवाल नहीं है, जल्द से जल्द आप वहां चुनाव करा सकते हैं और चुनाव कर के मनीपुर के लोगों की जो ख्वाहिश है कि अपने प्रशासन का काम खुद वे लोग संभाले, इसका मौका आपको जल्द से जल्द देना चाहिए, और जब तक आपके हाथ में मनीपुर के प्रशासन की रेस्पांसिबिलिटी है, आप वहां की स्कीम्स को जल्द से जल्द लागू करवाने की कोशिश कीजिए । लोकटक प्रोजेक्ट के बारे में और उसके साथ हैन्डलूम का सूत वगैरह सप्लाई करने के बारे में, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के बारे में, साथ ही साथ कम्युनिकेशन का जो मनीपुरियों का सवाल है, इन सबके लिए आप जल्दी क़दम उठाएं । जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है वहां तक कोई ट्रेन नहीं है, काछार से होते हुए एक रेल लाईन मनीपुर तक ले जाने के लिए काफी दिनों से मांग है, केन्द्र सरकार ने कोई स्कीम भी बनाई थी लेकिन आज तक वह काम हो नहीं पाया है । 12 घंटे लगते हैं मनीपुर से बस में दीनाजपुर रोड पहुंचने में और दिल्ली जाना हो या कलकत्ता जाना हो तो

5–7 दिन लग जाते हैं, इसलिए मजबूरन मनीपुर के लोग बाई प्लेन मनीपुर से कलकत्ता जाते हैं, खास कर इस वजह से भी कि वहां मौसम की हालत यह रहती है कि लगातार पांच-छः महीने बरसात होती है और इस हालत में कलकत्ता से हफ्ता में दो-तीन दिन विमान सर्विस भी कैंसल रहती है। तो मनीपुर के लोगों को बाहर आने जाने की सुविधा के लिए विमान व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ विमानयात्रा के टिकट का रेट मनीपुरियों के लिए कुछ किफायती होना चाहिए क्योंकि काफी हद तक यह उन लोगों की मजबूरी ही है जिसकी वजह से विमान से उन्हें जाना पड़ता है, कोई शौक से नहीं जाते। तो इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिए जब तक आपके हाथ में मनीपुर का प्रशासन है। तब जाकर मनीपुर आगे बढ़ेगा और इस क्षेत्र में जो एन्टी सेन्टर फीलिंग कुछ नौजवानों में बढ़ रही है उसको आप रोक पाएंगे।

श्री नवल किशोर : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा कोई इरादा मनीपुर पर बोलने का नहीं था मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कल का दिन बड़ा शुभ दिन था कि नये नये नाम-संस्कार किए गए और मेरे भाई पन्त जी को एक माता की उपाधि भी दी गई, क्योंकि एक शुभ दिन था, खुशी का दिन था। आज श्रीमन्, बड़ा अशुभ दिन है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में फिलहाल जनतंत्र समाप्त है और उसकी अवधि बढ़ायी जा रही है। अब मनीपुर का सवाल आ गया, उड़ीसा का भी आ गया इसलिए आज भारतीय जनतंत्र के लिए बड़ा अशुभ दिन है और मैं चाहता था कि यह अशुभ काम पन्त जी न करते और मंत्री स्वयं होते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि पन्त जी तो बच्चे हैं, छोटे हैं, नौजवान हैं, उनको श्राद्ध का काम अभी नहीं करना चाहिए था।

श्रीमन्, पंत जी ने कहा कि मैंने आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का समर्थन किया। सही बात है, वहां स्थिति ऐसी थी। मैं चाहता हूं और चाहता था कि आन्ध्र प्रदेश का इन्टिग्रेशन कायम रहे। मुझे ऐसा लगा कि शायद यह राष्ट्रपति शासन, गोकि यह अनडिमोक्रेटिक है, गलत है, लेकिन एक क़दम हो सकता है कुछ प्रश्नों को हल करने का। परन्तु मनीपुर की स्थिति दूसरी है। पन्त जी इत्तिफाक करेंगे कि वहां कोई ला एण्ड आर्डर की समस्या नहीं थी, वहां सिर्फ समस्या यह हुई कि जो रूलिंग पार्टी अपोजिशन की थी, उसमें कुछ डिफेक्शन्स हो गए, कुछ आदमी टूट गए। अब वह डिफेक्शन्स कैसे हुए, श्रीमन् इसको आप भी खूब समझते हैं क्योंकि आप बड़े राजनीतिज्ञ हैं, और पन्त जी इस बात को मानेंगे नहीं मगर यह सही बात है कि कांग्रेस के लोगों ने वहां पर उन डिफेक्शन्स को कराया। पन्त जी बात बड़ी खूबसूरती के साथ कहते हैं। उन्होंने श्री कमलापति त्रिपाठी के बारे में कहा था कि उन्होंने अब त्यागपत्र बड़ी उदारता के साथ दिया और पन्त जी यहां के सम्बन्ध में कह सकते हैं कि हम वहां पर गवर्नमेंट बना सकते थे क्योंकि डिफेक्टर्स हम में शामिल होना चाहते थे, फिर भी हमने गवर्नमेंट नहीं बनाई। एक छोटे भाई के नाते मैं तो चाहता हूं कि उन्हें बधाई देता, मगर वे ऐसे दल-दल में फंस गये हैं कि उनकी नीयत साफ दिखलाई नहीं देती है। क्योंकि अगर उड़ीसा में उन्होंने सरकार बना दी होती विरोधी दलों की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मणिपुर में भी सरकार बन जाती। चूंकि उन्होंने उड़ीसा में गल्ती कर दी थी और उस गल्ती को ताकत देने के लिए ताकि वह गल्ती साबित न हो, उन्हें मणिपुर में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह बात नहीं है। अगर उड़ीसा में सरकार बन जाती तो मध्य प्रदेश और गुजरात भी इनके हाथ से चला गया होता।

श्री नवल किशोर : श्रीमन्, मैंने अपनी पिछली स्पीच में भी यह बात कही थी कि किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के माने यह होते हैं कि जब असेम्बली को डिजौल्व कर दिया गया तो जितनी जल्दी हो सके, हम को वहां पर चुनाव करा देना चाहिये। मैं पन्तजी से

[श्री नवल किशोर]

यह जानना चाहता हूं कि वे कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के अन्दर जहां बड़े बड़े इश्यू के ऊपर पार्लियामेंट डिजौल्व हो गई हो और दो या चार महीने के अन्दर वहां पर चुनाव न हुए हों। तो श्रीमन्, डिस्सोलयूशन के माने यह होते हैं कि हम फौरन जनता के पास जायं, लेकिन इस तरह की बात मणिपुर के सम्बन्ध में नहीं हुई।

श्री पीताम्बर दास जो ने लिमिटेड डिक्टेटरशिप की बात कही। श्री रणबीर ने कहा कि आज प्रधान मंत्री जी ने फ्रीडम फाइटरों की सभा में यह बात कही है कि हमारी इस तरह की कोई मन्शा नहीं है। उन्होंने इस बात का खंडन किया, मुझे इस बात की खुशी है। मगर एक बात और भी है और मुझे इस सम्बन्ध में एक शेर याद आ गया है :—

हम वक्त पे नजरें रखते हैं, हमने दौरे जमाना समझा है।

कुछ मसलहतन कुछ मजबूरन, कातिल को मसीहा कहते हैं।

श्रीमन्, कहने का मतलब यह है कि आज सोवियट रूस में डिक्टेटरशिप है और आप मेरी इस बात से इत्तिफाक करेंगे, पंत जी भी इत्तिफाक करेंगे कि वहां के बारे में वहां के लोग कहते हैं कि वहां पर पीपुल्स डैमोक्रेसी है। याहिया खान ने पाकिस्तान में फौजी शासन स्थापित किया और उसने उसको बेसिक डेमोक्रेसी का नाम दिया था। इंडोनेशिया में भी डा० सुकार्णो के जमाने में सेमी डिक्टेटरशिप थी और उसको गाइडेड डेमोक्रेसी कहा गया था। क्या पन्त जी भी इस देश में इसी तरह की बात करना चाहते हैं? राष्ट्रपति शासन भी एक प्रकार से अपनी तरह की लिमिटेड डिक्टेटरशिप ही है।

(Time bell rings.)

श्रीमन्, मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म कर दूंगा। जहां तक मणिपुर का सवाल है, वहां पर जल्द से जल्द चुनाव कराये जायं। दूसरी बात यह है और जैसा मेरे दोस्त ने अभी जो मणिपुर से आये हैं कहा कि वहां पर जब मेडिकल कालेज नहीं था तब उनकी सीटें मेडिकल कालेज में दुगुनी थीं, लेकिन जब वहां पर मेडिकल कालेज खुल गया तो सीटें 11 ही रह गईं यानी पचास प्रतिशत सीटें रह गई। यह बात देखने की है।

एक बात जो मेरे दोस्त ने कही श्री बरबोरा जी ने भी कही कि मणिपुर एक आइसोलेटड जगह है, लेकिन वह बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सौन्दर्य से भरा हुआ है, पिछड़ा है और एक बोर्डर स्टेट है। वहां पर जाने का केवल साधन हवाई जहाज ही है। अगर मौसम खराब हो जाय, जैसा कि आज वहां पर है, तो फिर कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वहां पर पहुंचा जाय। मैं चाहता हूं कि इस नई स्टेट पर केन्द्रीय सरकार की विशेष कृपा होनी चाहिये। जैसा आपने फरमाया कि यह आन्ध्र प्रदेश एक मालदार स्टेट है, लेकिन वहां पर गरीब लोग बसते हैं। मणिपुर जो है वह एक खूबसूरत जगह है, उसका अपना कल्चर है, उसका अपना गाना है, नृत्य है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वह पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो उन्होंने मांग की है कि मणिपुर को कम से कम इम्फाल तक ट्रेन से जोड़ दिया जाना चाहिये, वहां पर सड़कें बननी चाहिये ताकि वहां के लोग और बाकी देश के लोग एक दूसरे के वहां आ जा सकें और वहां का व्यापार भी बढ़ सके। वहां के लोग गरीब है और प्रेजीडेन्ट रूल में वहां के लोगों की गरीबी को दूर किया जाना चाहिये। (Time bell rings) श्रीमन्, मैं एक यह बात कह कर खत्म करना चाहता हूं कि मणिपुर में शीघ्रातीशीघ्र चुनाव करायें जाएं ताकि वहां की जनता को अपनी चुनी सरकार मिल सके।

SHRI HAM1D ALI SCHAMNAD (Kerala) : Mr. Vice-Chairman, Sir, democracy means, as everybody knows, the rule of the people, for the people and by the people. But, unfortunately what we find here in India is the rule of the Centre, for the Centre and by the

Centre or the rule for you people, of you pedple and by you people. If that is so, Sir, we do not know where we will reach. The image of our country in the world as a democratic country is good. As a democratic country India definitely had a name and even today we have a very good name in the democratic world. Our beloved leader, the late Shri Jawaharlal Nehru, the late Sardar Patel and also, Sir, the father of our beloved Home Minister, Shri Pant, all these people did maintain democracy at any cost. They did not think of doing anything in an undemocratic way. Today, what we find in India is that article 356 of the Constitution is being brought into force in one State after another. We can understand if it is imposed in times of emergency and that too for the minimum period that is necessary. But here article 356 is introduced and is in force not only **for** the minimum period, but also for the maximum period that is required for the ruling party. You can take **a** liberal view of this article in the constitution. If it is taken in the right spirit, you will find that it is only meant for the emergency period and not for an ordinary or a normal period. Here, Sir, you will find that the Proclamation issued by the President on the 28th March 1973 is sought to be extended for a further period of six months with effect from the 14th November, 1973 under article 356 in relation to the State of Manipur. So. we are going to have the President's Rule there for some more time and it is not only in Manipur, but also in Andhra Pradesh, which is your State. So, Sir, we are giving a licence to the Central Government to rule some of the Stales in India as they like. The Congress party had an overwhelming majority in Andhra Pradesh and in spite of that they could not rule Andhra and so also in Orissa. And, in U.P., about which I need not tell you, the Assembly is J there, but the Government is not there. ' This is the state of affairs that is pre- | vailing in India and this tendency should not be encouraged. Anybody who has got any love for democracy, who wants j to see that democracy is preserved in India, cannot but decry this tendency and 1 do not know what will happen to democracy in India in future if we allow this State of affairs to continue.

Now, I analyse the conditions in. various States. In Andhra Pradesh, the Congress was having an absolute majority, but, at the same time, they could not carry on there and it is the same case with U.P. also. U. P. Assembly is not dissolved. But the Governor is in the helm of affairs. This is a new experiment. So also in Orissa. The reasons are very clear. Firstly, as it has been said by Mr. Mariswamy already, because leadership is being imposed from the Centre to the States — unwanted leaders. After all, who is the leader? The leader has to be elected by the people. I cannot go and say in my State : I am your leader. People there will have to say: You are our leader. Leader has to be elected by the people. Then only he will be resepcted by the people. But it is not so, Sir. In Mysore, they have a thumping majority but they are on the verge of a very bad position. I do not say that President's rule is to be imposed; democracy is there. But, at the same time, we do not know what is going on there. Many things are being said about Mysore today. I find, and I really feel, when we analyse all these facts and figures, that the Congress, where they do not have a majority, have a stable government.

Take, for example, Kerala. The Congress Party does not have a majority there; they are in a minority in Kerala. But, at the same time, there is a stable government, a strong government, in Kerala for the last three years, and it will rule for five years. They do not have an absolute majority in Kerala as they have in some other parts of the country.

Now, the people know that it is not good in the interest of democracy to give a thumping majority to the ruling party, the Congress, because the result is President's rule there. So, that is their practical experience.

I do not want to prolong my speech. I only appeal to the Home Minister and to the Government to see that an opportunity is given to the people of Manipur to elect their owft

[Shri Hamid Ali Schamnad]

leaders, to elect their own goverment, as early as possible. I appeal to them not to use the provisions of the Constitution very liberally and to the maximum extent. Use provisions of the Constitution to the minimum extent that is necessary. Do not go on prolonging it for another, six months, another six months, and so on. Use them not more than six months and give the people there an opporunity to rule themselves, with these words, Sir, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Shri Yadav. Three minutes.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं करते हुए कुछ प्रश्न श्रीमान् पन्त जी से पूछना चाहता हूं। पन्त जी यह समय क्यों बढ़ाना चाहते हैं और क्यों नहीं अविलम्ब चुनाव वहां पर कराते हैं जबकि संसद के सदस्यों की और वहां के लोगों की भी यह इच्छा है ?

आज यह विदित है कि मनीपुर के शासन में मनीपुरियों का हाथ नहीं है। इसीलिए मैं पन्त जी से यह भी जानना चाहूंगा कि अभी जो वहां पर नौकरशाही का शासन है उस नोकरशाही के शासन में मनीपुरियों का प्रतिनिधित्व क्या है ?

एक प्रश्न यह है कि वहां पर उच्चस्तरीय शिक्षा की स्थिति क्या है? आज यह प्रश्न इसलिए उपस्थित हुआ कि जो मेडीकल कालेज खुला है उसके संबंध में यह चार्ज लगाया गया कि उनके प्रदेश में मेडीकल कालेज होते हुए भी उन्हे मात्र ग्यारह स्थान प्राप्त है। इसी लिए हमारा यह सवाल है कि उच्च स्तरीय शिक्षा की वहां पर क्या स्थिति है।

इसी संदर्भ में मैं एक प्रश्न और गृह राज्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा। वहां की उच्च स्तरीय सर्विसेज में मनीपुरी लोगों की क्या स्थिति है ?

वहां का एक मात्र उद्योग धंदा हथ-करघा है। सरकार ने जब से सूत का राष्ट्रीयकरण किया तब से देश के अन्य स्थानों में जिस प्रकार से हथ-करघे चलना बन्द हो गये और एक हाहाकार मच गया और इसके कारण यहां पर भी कई बार ध्यानाकर्षण रूप में वह चीज सामने आई, उसी प्रकार मनीपुर में भी स्थिति उत्पन्न हुई। यह भले ही हो कि यहां पर उसकी आवाज जिस बुलन्दी से उठनी चाहिए थी उस बुलन्दी से नहीं उठी। आज भी वहां घर घर में जो एक मात्र उद्योग है उसकी स्थिति स्टेपिल यार्न की कमी की वजह से खराब हुई है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में वहां की वर्तमान स्थिति क्या है?

खेती भी वहां का प्रथम कारोबार है। आजतक प्रगति के नाम पर चाहे वह सिंचाई कहिये, बंडिग कहिये, फेंसिंग कहिये, लेवलिंग कहिये, कुछ भी नहीं हुआ है। एलेक्ट्रीसिटी तो वहां है ही नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी स्थिति में क्या सुधार वहां पर हुआ है।

श्रीमन्, मनीपुर में नागा की समस्या नहीं लेकिन डेढ़ लाख के ऊपर या दो लाख के करीब वहां नागा हैं और चलते फिरते दिनों में हमने वहां पर नागाओं की समस्या सुनी है। यहां से भी नागा चीन जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेकर यहां आते भी है और उत्पात मचाते है। इसलिए उनकी समस्या की क्या स्थिति है यह भी हम जानना चाहेंगे।

दो तीन सवाल और हैं। वास्तव में आज मैं सवाल ही करना चाहूंगा। भारतीय संस्कृति की महिमा अपरंपपार है और आज भी हमारा देश दुनिया में इस गरीबी, बेकारी और कमजोरी में जिन्दा है तो अपनी संस्कृति के बल पर जिन्दा है। इस संस्कृति को देखने के लिए इस संस्कृति को समझने के लिए दुनिया के लोग आज भी भारत में आते हैं। और उसमें मणिपुर को बहुत बड़ा श्रेय है, उस संस्कृति जिस में एक ही चीज उन्होंने अपनायी है और वहहै नृत्य। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब मणिपुर का नृत्य

बहुत मशहूर है और वहां का लोकनृत्य भी तो क्या सरकार के ध्यान में यह चीज कभी आयी है कि उस की उन्नत्ति की जाय ? और अगर यह बात सरकार के ध्यान में आयी है तो उस के लिए सरकार ने क्या किया है ।

श्रीमन्, वहां कुछ उद्योग और भी है कि जो बहुत जबरदस्त ढंग से वहां विकसित हो सकते हैं और उन में एक है तसर का उद्योग । मैं जानना चाहूंगा कि गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान क्या इस ओर गया है ?

इसी तरह से यातायात का सवाल है । देश की सुरक्षा की बात भी मैं उसी के साथ करना चाहता हूं । सुरक्षा और यातायात के साधनों का अगर वहां विकास किया जाय तो उन के कारण वहां आवागमन के साधनों का विकास होगा और वहां उन के कारण काश्मीर की तरह एक पर्यटन के उद्योग का विकास हो सकता है और मैं जानना चाहता हूं कि उस ओर भी उन का ध्यान है या नहीं ।

और श्रीमन्, भारतवर्ष की आजादी में जो आजाद हिन्द फौज का कांट्रीब्यूशन है उसे भुलाया नहीं जा सकता । वह आजाद हिन्द फौज इंफाल तक आयी थी और वह इम्फाल जो नेता जी के चलते प्रसिद्ध हुआ क्या उस चिरस्मरणीय स्थान के लिए हम कुछ ऐसी यादगार की चीजें करना चाहते हैं जिस से कि सचमुच में हम नेता जी को स्मरण कर सकें । एक शब्द और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करुंगा ।

मणिपुर अपने इस राष्ट्र के साथ अपनी एकात्म समता का बोध कर सके ऐसी कुछ बात क्या आप ने इस राष्ट्रपति शासन में की है । यदि की है तो उस का उल्लेख मंत्री जी अपने उत्तर मे अवश्य करें क्योंकि मैं ने अभी सुना है कि वहां पर प्रांतीयता के भाव उमड़ रहे हैं और केन्द्र के प्रति लोगों में रोष की भावनायें आज वहां ह इसि लिए मैं ने यह सवाल रखा है ।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल (बिहार) : एक बात मैं यह जानना चाहता हुं कि क्या यह बात सही है कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चुनाव होने हैं लेकिन कौंसिल वहां पर नहीं बनने दी जाती है । यह बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

SHRI K.C. PANT : Sir, I am grateful to the hon. Members who have participated in the debate for pointing to many important aspects of the life of Manipur, apart from the political aspect. Manipur is a very beautiful State. It is a State which gives us a good example of integration between hill people and the plain people. It consists of a valley surrounded by hills on all sides and, for a long time, the hill people and the valley people have lived together. It is a border State and is important to the security of the country. It is a State which has a long history, not as a State perhaps, but in the history of India it has had a place even in ancient times. It has a rich culture to which Shri Yadav referred. He mentioned in particular the Manipur dance. It is one of the foremost schools of dancing in India today.

Sir, the economic aspects of development and so on to which a reference was made are important and within the limitation of time available during the President's Rule all efforts will be made to concentrate on some areas of development which can produce quick results and also speed up some of the long-term projects. All the projects which were mentioned here are long-term projects and the Lohtak project is a project which is due for completion in 1975. So all that can be done now during the President's Rule is to speed up the execution of the project and I can assure Shri Salam Tombi that this will be attempted.

Many hon. Members do not know that there was a severe drought in Manipur also along with various parts of the country.

SHRI SALAM TOMBI: Sir, I am afraid, the Lohtak project will not be completed even after three grace years.

SHRI K. C. PANT: Our effort will be to speed up the execution of the project as much as possible. This will be attempted during the President's Rule.

[Shri K. C. Pant]

Transmission of light is to be strengthened. It is a very big project. As my hon. friend knows, we have been trying to speed up its execution in the last few months but I must point out that a large part of concentration of the administration has been on drought and the drinking water situation there. He knows fully well that water has reached every village. I think, he will agree that the administration has tackled this problem of water famine with commendable success considering the size of the problem and the nature of the pro-the problem and the nature of the pro-it perhaps do not realise it but it is not a questiou of irrigation, it is a question of drinking water in many village, this is one of the major problems of Manipur.

Sir, he has raised the basic political

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आन्ध्र प्रदेश के बारे में आप तैयारी करके आए थे, मनीपुर पर आप तैयार नहीं हैं।

श्री के० सी पन्त : मनीपुर के बारे में है आपने जो बहस की उसका कोई आधार ही नहीं है। मैं बताऊंगा आपको।

question. There is no political question here. He does not perhaps fully appreciate the fact that the President's Rule was imposed because at that time it was thought it was not possible to restore popular government. The Assembly is not in suspension, it has been dissolved. The only course open to us, if you want to have the Assembly, is to have elections. Now the Constitution requires that after the census is complete, the constituencies in the whole country are delimited. New fresh electoral rolls are drawn up. The territorial area of the constituency is changed. It is necessary once again to come to the Parliament to decide what will be size of the Parliament. For that Parliament has to pass a law. The number of seats in Manipur may be affected by that law. So this is not a matter about which you can criticise the Government. This is a matter which the Election Commission is now taking up.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : पन्त .जी बंगलादेश की घटना के बाद चुनाव के •समय कांग्रेस की स्थिति बड़ी अच्छी थी इसलिए तुरन्त चुनाव हो गए लेकिन आज जो स्थिति सूखे को लेकर, अकाल को लेकर बनी है यह स्थिति आपके अनुकुल नहीं है इसलिए आप कोई "एलिबाई" बनाते जा रहे हैं। और कोई दूसरा कारण नहीं।

श्री पीताम्बर दास : ऐसा इम्प्रेशन है।

श्री के० सी० पन्त : अब यही यादव जी और पीताम्बर दास जी की समझ में फर्क है। पीताम्बर दास जी ने इस ढंग से कहा है जिसमें कि वे तो समझते हैं, दूसरा नहीं समझता है यादव जी इस ढंग से कहा है जिसमें कि वे तो समझते हैं,

Sir, the fact of the matter is that it is not possible at this point of time to hold the elections. The constitutional processes which have to be completed after a census operation have not been completed and they will require a few more months to be completed. At best some time early next year the Election Commission will be in a position to hold the elections in Manipur. Really there is nothing to discuss on that aspect of the question.

Some reference was made as to how the State came under President's rule Initially and I think everybody who spoke from the Opposition tried to suggest that this was done somehow to serve party ends. I will remind Shri Salam Tombi Singh that President's rule was brought about in Manipur only because his party and other parties who were in coalition there could not hold together. It was not our fault that they were unable to keep the Government going. In fact for eleven long days attempts were made to win back those who had defected and to win back some of the Congressmen also but it could not be done. There was some kind of a kidnapping. There was a Government in power with its police and everything and to talk of kidnapping

is ip have a very poor opinion of your own .Government in power. Therefore there is no question of bringing down the Government; at least we were not interested and I can tell Mr. Salam Tombi Singh that the Centre was quite happy to have his party's Government continue there. Mr, Alimuddin was the Chief Minister; we had good relations with him and, in fact we had advised our own partymen not to be in a hurry. We had told them repeatedly that we would like this Government to continue but the Government could not keep itself together and therefore this situation was created. Now the question is why we did not allow a Congress Government to come into being. That could have been done but if we had not done it certainly you should not blame us for this particular point because I do not think that you were interested in the Congress Party coming into power. You were happy when we allowed President's rule to be imposed rather than allow the Congress Party to form a Government. This is the fact of the situation and I think Mr. Salam Tombi Singh will agree with it. Therefore we had done what he wanted us to do at that time. Now since elections could not be held it is being extended. So I just do not see where the political criticism comes in. There is no party interest involved in this matter.

Some reference was made by Mr. Salam Tombi Singh to the number of seats in the Medical College and Nawal Kishoreji also referred to it. The share of Manipur in the Imphal Medical College is not 11 but 25 but we are trying to get more seats in other States for Manipur people. I might tell him that last night I saw some papers in this regard and I have sent them to the Health and Family Planning Minister last night itself and if it is possible to help Manipur I would certainly exert whatever personal influence I have with the Health Minister to try to get it done. So there is no question of not being sensitive to Manipur's requirements. I realise that it requires doctors and I hope those doctors will be prepared to go to the villages where they are needed.

SHRI PITAMBER DAS: You can bring those people to other colleges. It will be a very good step towards national integration.

SHRI K. C. PANT : In fact that is one of the reasons why we encourage boys from all regions to come to other States and this whole North Eastern region in this respect offers opportunities and also presents certain difficulties. Sir, one of the difficulties which has confronted the Administration there more recently is the activity of the Naga underground and some reference was made to it by Shri Mandal. He has gone out now but the point is well taken. There have been several incidents and it points the need for greater vigilance. The number of persons killed may not be many but there have been many incidents and the security forces there are very vigilant and we realise that such incidents ultimately cause unhappiness to the people there. The security froces and the civil authorities there will do everything in their power to see that this kind of depradation or ambush is not allowed.

Sir, there was some reference by Mr. Barbora to road communications and he referred to the need to strengthen road communications.

SHRI GOLAP BARBORA: Subsidised air transport.

SHRI K. C. PANT: Subsidised air transport is not an easy matter for me to answer. In such a large country there are many far-flung regions and whether to subsidise or not to subsidise is one of the difficult questions. I understand the need to establish communication links which offer quick transport to the majority of the people. Even if you subsidise air transport it cannot be used by the common man. We should have road communications and good road communications. Therefore, in recent months a sum of Rs. 54.22 lakhs has been spent and utilised mainly on improvement of roads like the Imphal-Ukhrul road, Imphal-Tamling road, Im-phal-Tiddim road and the Imphal-Sugnu road. Perhaps my hon. friend knows that just now the communication is

[Shri K. C. Pant]

through Kohima, btrt now the intention is to have a direct link from Imphal also. In the terrain which obtains there it does take some time, but this is definitely one of the schemes before us. This is being implemented.

Apart from that, the question of the number of Manipuris in the administration was raised. There are two Manipuris who are Secretaries out of 5 Secretaries. All the Joint Secretaries are Manipuris. They are local men. Out of 5 Deputy Commissioners, three are local Manipuris. The Advocate-General is a Manipuri. I know the sensitiveness of the people in that area. Certainly we try to encourage local people consistent with the need to have administrators from all over the country distributed to all the States. This is not peculiar to Manipur. In every State in the country we have administrators, IAS boys, for Instance. They are distributed all over the country. We have boys from Kerala working in Kashmir or working in U.P. We have boys from U.P. working in Assam or Maharashtra and some in the Andaman and Nicobar Islands. This is the way that we deliberately plan for the distribution of administrators all over the country. I think it is a very healthy thing. I think the people of Manipur would also welcome it, particularly when they realise that these administrators have nothing but the good of the people of Manipur at heart, and they are doing their level best to integrate themselves into the conditions. They are with the people there and are taking up all the projects in earnestness. I think these were some of the points which were raised. While there are a few other matters, I would only mention one point which is of some importance. It was raised by Mr. Barbora and that is about yarn which is of great importance—to the handloom industry of Manipur. It is very vital to its economy. In the beginning yarn did present some difficulties. In recent weeks for some time there was dislocation in the distribution of yarn. I have just been informed that this dislocation has been set right and the distribution of yarn has improved greatly in the last few weeks. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): The question is :

"That this House approves the continuance of the Proclamation issued by the President on the 28th March, 1973, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Manipur, for a further period of six months with effect from the 14th November, 1973."

The motion was adopted...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B.

): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at forty minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 10th August, 1973.

A.M. tomorrow.

The House then adjourned at forty minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 10th August, 1973.

): The House stands adjourned till 11